



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3-- उप-खण्ड (i)
PART II--Section 3 --Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365]
No. 365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 1995/भाद्र 17, 1917
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 1995/BHADRA 17, 1917

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1995

सांका०नि० 626(अ).—राष्ट्रपति, अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र वित्त आयोग (सेवा शर्तें और अन्य प्रकीर्ण उपबंध) नियम, 1995 है ।

(2) ये अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे,

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” और “सदस्य” से नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) “आयोग” से अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है;

(घ) “राजपत्र” से भारत का राजपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) “विनियम” से अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(च) “धारा” से विनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) “संघ राज्यक्षेत्र” से अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

3. वित्त आयोग की संरचना (1)—वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राष्ट्रपति अवधारित करे।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशित आदेश से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी :

परंतु कोई व्यक्ति जो—

- (क) संघ या किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् का सदस्य है; या
- (ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य या संसद् सदस्य है; या
- (ग) किसी संघ राज्यक्षेत्र की पंचायत या नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या कोई कर्मचारी है,

आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

4. नियुक्ति के लिए अर्हताएं :—(1) अध्यक्ष का नियुक्ति के लिए चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्हें लोक प्रशासन में या वित्त और आर्थिक प्रशासन में या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन का अनुभव है।

(2) सदस्य का नियुक्ति के लिए चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनसे पास—

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान है; या
- (ख) स्वायत्त शासन, जिसके अंतर्गत पंचायत या नगरपालिका भी है, के संस्थाओं के वित्तीय मामलों में और इसमें प्रकाशन का व्यापक अनुभव है; या
- (ग) अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है।

5. नियुक्ति की अवधि :—धारा 186 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति में प्रसाद पर्यन्त ऐसी अवधि के लिए जो नियम 1 के उपनियम (2) के अधीन जारी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेंगे

6. अध्यक्ष और सदस्य होने के लिए अनर्हता :—कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब अनर्हित होगा यदि वह—

- (क) भारत का नागरिक नहीं है, या
- (ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, या
- (ग) अनुमोचित दिवालिया न्याय निर्णयी किया जाता है, या
- (घ) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्बलित है दोष सिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, या
- (ङ.) राष्ट्रपति के समाधानप्रद रूप में संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन में ऐसा वित्तीय और अन्य हित रखता है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

7. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें—(1) अध्यक्ष और सदस्य जैसा कि राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन जारी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट करे, आयोग की पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा करेगा।

(2) अध्यक्ष और सदस्य को क्रमशः 8,000 रुपए और 7,500 रुपए प्रतिमास के नियत वेतन का संदाय किया जाएगा :

परंतु यदि किसी सदस्य की नियुक्ति आयोग में अंशकालिक सेवा करने के लिए की जाती है तो उसे 4,000 रुपए प्रतिमास की नियत फीस का संदाय किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य के अन्य निर्बंधन और सेवा की शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम श्रेणी के अधिकारी को लागू होती हैं।

8. त्यागपत्र—अध्यक्ष या सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

9. हटाया जाना—राष्ट्रपति, राजपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित आदेश द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेंगे यदि वह व्यक्ति—

(क) नियुक्ति के पश्चात् नियम 6 में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन हो गया है, या

(ख) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसका पद पर बने रहना अवांछनीय हो गया है :

परन्तु नियम 6 के खंड (ड.) के अधीन या इस नियम के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में सुने जाने का व्यक्तिगत अवसर न दिया जाए ।

10. अध्यक्ष के पद पर रिक्ति—यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष प्राधिकृत अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो आयोग का ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह पद ग्रहण नहीं कर लेता या अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता ।

11. आयोग के कर्मचारिवृन्द—(1) प्रशासन आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा जो विनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सचिव और अन्य कर्मचारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो किसी सरकारी अधिकारी/समतुल्य श्रेणी के किसी पदधारी को लागू होती हैं ।

12. आयोग का मुख्यालय—आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

13. प्रक्रिया—आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, जिसमें उसकी बैठकें आयोजित करना भी है स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा ।

14. आयोग के कृत्य—आयोग मंत्रालय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्न के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा—

(क) वे सिद्धांत जिनसे निम्नलिखित शासित होने चाहिए—

(i) ऐसे करों, शुल्कों, पथकर फीसों का, जो पंचायतों को समनुदेशित की जा सकेगी या जो उनके द्वारा विनियोजित किया जा सकेगा, अवधारण;

(ii) भारत की संविधान निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान ।

(ख) पंचायत की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए अपेक्षित उपाय ।

(ग) पंचायत के ठोस वित्त के हित में उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामले ।

15. आयोग को निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वे सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को हैं; अर्थात् :—

(क) किन्हीं साक्षियों को समन करना और उनको हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई अभिलेख अपेक्षा करना;

(2) आयोग को किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में आयोग के विचाराधीन किसी विषय की विषयवस्तु के लिए उपयोगी और सुसंगत हो सकेगी और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाती है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अर्थ के भीतर ऐसी जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमा संघ राज्यक्षेत्र की सीमा होगी ।

16. आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना—(1) आयोग अपनी सिफारिश अन्तर्निहित करने वाली रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र राष्ट्रपति और प्रशासक को देगा ।

(2) राष्ट्रपति आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे ।

[फा सं० यू० 11022/1/94 यू०टी०एल०]

आर० आर० शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 1995

G.S.R. 626 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. *Short title extent and commencement.*—(1) These rules may be called the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995.

(2) They shall apply to the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory appointed under article 239 of the Constitution;

(b) "Chairman" and "Member" means the Chairman and member of the Finance Commission appointed under sub-rule (2) of rule 3;

(c) "Commission" means Finance Commission constituted under section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994;

(d) "Official Gazette" means the Gazette of India;

(e) "Regulation" means the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994.

(f) "section" means the section of the Regulation;

(g) "Union territory" means the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.

3. *Composition of the Finance Commission.*—(1) The Finance Commission shall consist of a Chairman and such number of other members, not exceeding four as the President may determine.

(2) The Chairman and the Members shall be appointed by the President by order published in the Official Gazette:

Provided that no person who is—

- (a) a member of the Council of Ministers of the Union or of a State or of a Union Territory; or
- (b) a member of a legislature of a State or of the Union Territory or member of Parliament; or
- (c) a Chairperson or Deputy Chairperson or member or an employee of a Panchayat or a Municipality of any Union Territory;

shall be eligible for appointment as Chairman or Member of the Commission.

4. *Qualifications for appointment.*—(1) The Chairman shall be selected for appointment from amongst persons who have experience in Public Administration or in finance and economic administration or in administration of Union Territories.

(2) The Member shall be selected for appointment from amongst persons who have—

- (a) special knowledge of the finance and accounts of Central Government or State Government, or of a Union Territory Government; or
- (b) wide experience in financial matters of institutions of self-government including the Panchayats or Municipalities and in the administration thereof; or
- (c) special knowledge of economics.

5. *Term of appointment.*—Subject to the provisions of section 186, the Chairman and Member shall hold office during the pleasure of the President for such period as may be specified in order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 3.

6. *Disqualification for being the Chairman and Member.*—A person shall be disqualified for being appointed as Chairman or Member if he—

- (a) is not a citizen of India; or
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) is adjudged as undischarged insolvent; or
- (d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the President, involves moral turpitude; or
- (e) has, subject to the satisfaction of the President, such financial or other interest in the administration of the Union Territory as his functioning as a Chairman or a member is likely to affect prejudicially.

7. *Conditions of Service of Chairman and Members.*—(1) The Chairman and Member shall, as the President may in each case specify in the order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 3, render whole time or part-time service to the Commission.

(2) The Chairman and Member shall be paid a fixed salary of Rs. 8,000 and Rs. 7,500 respectively per month :

Provided that if a Member is appointed to render part-time service to the Commission, he shall be paid a fixed fee of Rs. 4,000 per month.

(3) The other terms and conditions of service of the Chairman and the Members shall be such as are applicable to the highest grade Central Government officer.

8. *Resignation.*—The Chairman or Member may, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office.

9. *Removal.*—The President may, by order duly published in the Official Gazette, remove the Chairman or Member from the office if that person :—

- (a) after appointment has become subject to any of the disqualifications referred to in rule 6; or
- (b) has, in the opinion of the President, so abused the position of Chairman or Member as to render his continuance in office as Chairman or Member undesirable :

Provided that no person shall be removed under clause (e) or rule 6, or under this clause (h) of this rule until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

10. *Vacancy in office of Chairman.*—If the office of the Chairman becomes vacant or the Chairman is unable to discharge his functions owing to authorised absence, illness or any other cause, such Member of the Commission as the President may, by order published in the Official Gazette specify, shall discharge the functions of the Chairman until a new Chairman is appointed and assumes office or, as the case may be, the Chairman resumes his duties.

11. *Staff of the Commission*—(1) The Administrator shall provide the Commission a Secretary and such other employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under the Regulation.

(2) The terms and conditions of service of the Secretary and other employees referred to in sub-rule (1) shall be such as are applicable to a Government officer/Official of equivalent grade.

12. *Headquarter of the Commission.*—The Headquarter of the Commission shall be at New Delhi.

13. *Procedure.*—The Commission shall regulate its own procedure for discharge of its functions including holding of its meetings.

14. *Functions of the Commission.*—The Commission shall review the financial position of the Panchayats and make recommendations to the President as to—

- (a) the principles which should govern—
 - (i) the determination of taxes, duties, tolls, fees which may be assigned to or appropriated by the Panchayats,
 - (ii) the grants-in-aid to the Panchayats from the Consolidated Fund of India;
- (b) the measure needed to improve the financial position of the Panchayats;
- (c) any other matter referred to it by the President in the interest of sound finances of the Panchayats.

15. *Powers of the Commission.*—(1) The Commission shall have all the powers of a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;
- (b) requiring the production of any document;
- (c) requisitioning any public record from any court or office.

(2) The Commission shall have powers to require any person to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for or relevant to, any matter under consideration of the Commission and any person so required shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be deemed to be legally

bound to furnish such information within the meaning of Section 176 of the Indian Penal Code.

Explanation.—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the Union Territory.

16. *Submission of Report of Commission.*—(1) The Commission shall submit its report containing its recommendations to the President and the Administrator, as soon as possible.

(2) The President shall cause every recommendation made by the Commission together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before both Houses of Parliament.

[F. No. U-11022/1/94-UTL]
R. R. SHAH, Jt. Secy.

